



Publication
Edition
Date
CCM

The Pioneer
New Delhi
11/08/2024
47.76

Language
Journalist
Page no

English
PTI
6

Diversify ethanol production, Shah urges sugar mills

Diversify ethanol production, Shah urges sugar mills

PTI ■ NEW DELHI

Cooperation Minister Amit Shah on Saturday called on sugar mills to explore alternatives to sugarcane for ethanol production, pushing for a multi-dimensional approach to biofuel manufacturing. Speaking at an event organized by the National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF), Shah said India would achieve its 20 per cent ethanol blending target by 2025-26, ahead of the original 2030 deadline. The minister highlighted that the government's ethanol blending programme has helped reduce the country's crude oil import bill and address environmental concerns. "You need to be futuristic and



look at opportunities and expand. Ethanol can be made from multiple sources," Shah said, urging cooperative sugar mills to shed their "orthodox" approach and explore alternative feedstocks such as maize and bamboo. Shah said about 1,000 crore litres of ethanol is required for blending, and the necessary infrastructure to achieve this target is in place. He emphasised the need for

sugar mills to modernise and adopt new technologies, citing potential export opportunities once the Global Biofuels Alliance is established.

The minister challenged NFCSF to expand its operations, suggesting the federation to set up one cooperative sugar mill for every three districts in four states within a year.

Shah also advised NFCSF to hire professionals to guide loss-making cooperatives and set a target of increasing mills' annual turnover by 25 per cent in two years.

"We have a habit of working inefficiently and seeking help from the government. The government will be willing to help more if you work efficiently.Make a dynamic Federation, not a demand-

driven Federation," he added.

The push for diversification comes as India seeks to reduce its dependence on fossil fuels and promote sustainable energy alternatives.

Shah also gave away the NFCSF awards for best performing cooperative mills under different categories.

NFCSF President

Harshvardhan Patil said the sector faces several challenges and demanded an increase in the minimum selling price of sugar, the rates of B-Heavy molasses and sugar syrup used for ethanol making, and export of 10-20 lakh tonnes of sugar.

The federation is in the process of preparing a roadmap for the sector for the next ten years and is likely to be ready by September 5.

Centre advances target for 20% ethanol-mixing in petrol to '25-'26

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Union home and cooperation minister **Amit Shah** on Saturday said govt has decided to advance the target of 20% ethanol blending in petrol from 2030 to 2025-26, appealing to sugar cooperatives to help achieve the target by ensuring that all sugar mills produce ethanol in two years, setting up multi-dimensional biofuels production plants and increasing efficiency of the existing sugar mills.

Referring to its quantitative growth potential where 1,000 crore litre ethanol would be required in the sale of 5,000



crore litre petrol, Shah said that increasing share of ethanol-blended petrol would reduce import bill of petrol and increase profits of sugar mills and sugarcane farmers in addition to saving the environment.

His remarks came a day after the cabinet approved modified Pradhan Mantri JI-VAN Yojana to keep pace with latest developments in the field of biofuels. The scheme aims to provide remunerative income to farmers for agri-residue, address environmental pollution, create local employment opportunities, and contribute to India's energy security and self reliance.

Shah was addressing a sugar conclave organised by the National Federation of Cooperative Sugar Factories. He said govt is ready to support setting up of multi-dimensional biofuels production plants, underlining that number of cooperative sugar mills should be increased by mapping the area of sugarcane sowing across country under the 10-year roadmap.

"Sugar industry produced 38 crore litre ethanol earlier & there was limited use of it, which has increased to 370 crore litre today," he said.

Our aim is to transfer the entire profit of sugar production to the farmers' account:
Shah

चीनी उत्पादन का पूरा मुनाफा किसानों के खाते में पहुंचाना हमारा लक्ष्य : शाह

कहा-सभी सहकारी चीनी मिलों में हो इथेनॉल उत्पादन, गन्ने का तलाशें विकल्प

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, देशभर की सभी सहकारी मिले इथेनॉल का उत्पादन करने वाली हों, मगर इसके लिए गन्ना का विकल्प तलाशें। उन्होंने इसके साथ ही जैव ईंधन विनिर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। विकल्प के रूप में मक्का, टूटे चावल, सड़े फल और बांस से इथेनॉल बनाने वाली तकनीक पर काम करने का आह्वान किया है। साथ ही कहा, चीनी उत्पादन का पूरा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचे, यह लक्ष्य होना चाहिए।

शाह ने कहा, भारत की पहल पर जी-20 सम्मेलन के दौरान हुए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत पर्यावरण अनुकूल ईंधन के निर्यात में भी वरीयता हासिल करेगा। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ (एनएससीएसएफ) की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में महासंघ से इसके लिए दो साल का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। शाह ने चीनी मिलों के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, आपको भविष्यदर्शी होने और अवसरों को देखने और विस्तार करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर सहकारिता के आठ क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, चीनी उद्योग से इथेनॉल की प्राप्ति पहले 38 करोड़ लीटर होती थी और उसका सीमित उपयोग होता था, जो आज 370 करोड़ लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि इन सब का सीधा फायदा किसानों की जेब में गया है। शाह ने दावा किया पिछले 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है।



राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ के कार्यक्रम में राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान करते केंद्रीय मंत्री शाह।

गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 10 साल में 18 फीसदी बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर हुआ

शाह ने कहा, वर्ष 2013-14 में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 50 लाख हेक्टेयर था, जिसे मात्र 10 साल में लगभग 18 फीसदी बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। वहीं, गन्ने का उत्पादन 35.2 करोड़ टन था, जो आज 40 फीसदी बढ़कर 49.1 करोड़ टन हो गया है।

■ वहीं, उपज में 19 फीसदी और कुल चीनी उत्पादन में 58 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

सहकारिता मंत्री ने कहा, पीएम मोदी ने 2030 तक 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को हम

पांच साल पहले ही हासिल कर लेंगे लक्ष्य

2025-26 तक ही हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 5,000 करोड़ लीटर पेट्रोल की बिक्री में से इथेनॉल की जरूरत 1 हजार करोड़ लीटर हो जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार के इथेनॉल समिश्रण कार्यक्रम से देश के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है।

■ चीनी मिलों को 20 साल से लंबित 15,000 करोड़ रुपये की देनदारी निजात दिला दी...मोदी सरकार की ओर से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से चीनी मिलों के लिए बहुत कुछ करने का दावा करते हुए शाह ने कहा, लगभग 20 साल से लंबित 15,000 करोड़ रुपये की कर देनदारी से पीएम मोदी ने एक बार में ही चीनी मिलों को निजात दिला दी।

■ इसके साथ ही चीनी मिलों को उद्योग के बराबर ला दिया और एनसीडीसी की ऋण योजना में 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है, जिससे अगले 3 साल में 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा।

शरीर पर जीएसटी 28 फीसदी से पांच फीसदी किया... केंद्रीय मंत्री ने कहा, शरीर पर 28 फीसदी जीएसटी को घटाकर पांच फीसदी करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि एक प्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत नेफेड, कृषको, इस्को ने लक्ष्य तय किया है कि ये संस्थान भी अगले दो साल में अपना टर्नओवर 25 फीसदी बढ़ाएंगे। शाह ने कहा कि 10 साल के रोडमैप के तहत देशभर में गन्ना बुवाई के क्षेत्र को मैपिंग कर कोऑपरेटिव चीनी मिल की संख्या बढ़ानी चाहिए।

The prosperity of farmers is the goal of Modi government: Amit Shah

किसानों की समृद्धि ही मोदी सरकार का लक्ष्य : अमित शाह

नई दिल्ली, एनआइ : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) के चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही मोदी सरकार का लक्ष्य है।

शाह ने कहा, 2013-14 में गन्ने की खेती का रकबा 50 लाख हेक्टेयर था। इस समय यह 60 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस दौरान चीनी उत्पादन में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी उद्योग से इथेनाल की प्राप्ति 370 करोड़ लीटर हो गई है।

उन्होंने कहा, सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। आजादी के बाद सहकारिता आंदोलन



अमित शाह • फाइल फोटो

में जरूरी बदलाव नहीं हुए। इस कारण यह कुछ राज्यों तक सीमित रह गया। पीएम मोदी ने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इसके बाद से सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम हुआ। इन सबका फायदा किसानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि इथेनाल-ब्लेंडिंग के नीतिगत निर्णय से पेट्रोल का आयात बिल कम हुआ, पर्यावरण सुधरा, किसान लाभान्वित हुए और चीनी मिलों का भी मुनाफा बढ़ा। मोदी जी ने 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनाल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है लेकिन इस लक्ष्य को हम 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे।

Mills should look for alternatives to sugarcane for ethanol: Shah

चीनी सम्मेलन, राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह में बोले गृह मंत्री एथनॉल के लिए गन्ने का विकल्प तलाशें मिलःशाह

आह्वान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चीनी मिलों से एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का विकल्प तलाशने का आग्रह किया। साथ ही जैव ईंधन विनिर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ (एनएफसीएसएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि बीस प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 रखा गया है। हम 2025-26 में यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कहा कि सरकार के एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम से देश के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है। शाह ने चीनी मिलों के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एथनॉल कई स्रोतों से बनाया जा सकता है। सहकारी चीनी मिलें अपना रूढ़िवादी दृष्टिकोण त्यागें और मक्का व बांस जैसे वैकल्पिक कच्चे माल का उपयोग करें। शाह ने कहा कि मिश्रण के लिए लगभग एक हजार करोड़



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ द्वारा आयोजित चीनी सम्मेलन और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह के दौरान विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। •प्रेड

लीटर एथनॉल की आवश्यकता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है। उन्होंने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

गन्ना और चीनी का उत्पादन बढ़ा : शाह ने कहा कि 2013-14 में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 50 लाख हेक्टेयर था जिसे मात्र 10 साल में लगभग 18 प्रतिशत बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है।

पहले गन्ने का उत्पादन तीन करोड़ 52 लाख टन था, जो आज 40 प्रतिशत बढ़कर चार करोड़ 91 लाख टन हो गया है। इसी प्रकार उपज में 19 प्रतिशत और कुल चीनी उत्पादन में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डायवर्जन शून्य था, जो आज 45 लाख टन है। चीनी उद्योग से इथेनॉल की प्राप्ति पहले 38 करोड़ लीटर होती थी और उसका सीमित उपयोग होता था। पर आज 370 करोड़ लीटर हो गया है।

All profits from sugar production should reach the farmer's bank account

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने चीनी उद्योग संगोष्ठी को किया संबोधित चीनी उत्पादन का सारा मुनाफा किसान के बैंक खाते में पहुंचे

अपील: दो साल में देश की सभी सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल उत्पादन करने वाली हों

गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी चीनी मिलों को प्रदान किए राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार

पत्रिका व्यूरो

patrika.com

नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएफएफ) के 'चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23' समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर सहकारिता के आठ क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बहुत पुराने समय से हमारा देश सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है और सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है।



गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह।

अनेक राज्यों ने निभाई नेतृत्व की भूमिका

शाह ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अनेक राज्यों ने इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सहकारिता आंदोलन में जरूरी बदलाव नहीं हुए और इसके कारण ये कुछ राज्यों तक सीमित रह गया। शाह

ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद से सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इथेनॉल-ब्लेंडिंग के नीतिगत निर्णय से पेट्रोल का आयात बिल कम हुआ, पर्यावरण सुधरा, किसान लाभान्वित हुए और चीनी मिलों का मुनाफा बढ़ा।

चीनी उत्पादन सहित हर क्षेत्र में प्रगति

गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दिया है। किसान की समृद्धि ही मोदी सरकार का लक्ष्य है। चीनी उत्पादन का सारा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो साल में देश की सभी सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल उत्पादन करने वाली हो। चीनी उद्योग से इथेनॉल की प्राप्ति 38 करोड़ लीटर थी, जो आज 370 करोड़ लीटर हो गई है। पिछले 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने चीनी उत्पादन सहित हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को हम 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे।